पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

2015 का आपराधिक विविध संख्या 31934

थाना कांड संख्या-518 वर्ष-2013 थाना- पटना शिकायत मामला जिला- पटना से उत्पन्न मामला

==========

1. रमानी पांडे, पुत्र- श्री अशोक पांडे, निवासी- गांव- मलार, थाना- चारपोखारी, जिला- भोजपुर के निवासी हैं। वर्तमान में उज्जीवन फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में शाखा प्रबंधक के रूप में तैनात हैं।
2. अविनाश चौधरी, पुत्र- अमरेंद्र नारायण सिंह, निवासी- क्रेडिट मैनेजर, उज्जीवन फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता थाना- न्यू टाउन, जिला- कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
3. विभास चंद्र, पुत्र- रामचंद्र प्रसाद, निवासी- आशियाना नगर, थाना- राजीव नगर, जिला- पटना। वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापार प्रमुख, औद्योगिक ऋण पूर्वी क्षेत्रीय कोलकाता, थाना- नई कोलकाता में तैनात हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. मनीष रंजन @ मनीष कुमार रंजन, पुत्र- रामसेवक प्रसाद, निवासी- नखन मंगल अखाड़ा, थाना-मालसलामी, जिला-पटना के निवासी।

.... विपरीत पक्ष

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिएः श्री वाई. सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री प्रभाकर नाथ राय, अधिवक्ता

श्री आदर्श सिंह, अधिवक्ता

ओ. पी. नंबर 2 के लिएः श्री दयानंद प्रसाद देव, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष/दलों के अधिवक्ताः श्री अनिल कुमार सिंह नंबर 1, एपीपी

==========

भारतीय दंड संहिता---धारा 417, 418, 406, 420, 467, 468, 120, 182, 211---न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ चतुर्थ पटना के यांत्रिक संज्ञान आदेश के विरुद्ध ख़ारिज करने की याचिका–प्रतिशोधात्मक शिकायत का मामला किसी भी हलफनामे का समर्थन नहीं किया गया–झूठा पाया गया–संगठन को पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया –परोक्ष उद्देश्य से आपराधिक मामला–दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का स्पष्ट उदाहरण–अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देता है–केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के समान होगा जहां शुरुआत में कोई धोखा दिया गया–प्रारंभिक वादा करने के समय दोषी इरादे का अभाव, धारा 420 के तहत कोई अपराध नहीं–परोक्ष दायित्व के प्रबंध निदेशक के खिलाफ विशिष्ट आरोप के अभाव में, कंपनी को एक पक्ष के रूप में रखे जाने के अभाव में, प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती–परोक्ष दायित्व के लिए आरोप का गठन आवश्यक।

आदेश: धारा 417 व 418 के तहत प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं है–न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी-सह-अतिरिक्त मुंसिफ IV, पटना के संज्ञान के आदेश और आदेश के अनुरूप कार्रवाई के साथ रद्द कर दिया गया।

==========

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

ओरल जजमेंट

तारीखः 09-04-2024

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. वर्तमान निरस्तीकरण याचिका पटना सिटी पुलिस मामला संख्या 49/2012 से उत्पन्न शिकायत मामला संख्या 518/2013 में पारित दिनांक 24.02.2015 के आदेश को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत की गई है, जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी-सह-अतिरिक्त मुंसिफ चतुर्थ पटना ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 417 और 418 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया था।

3. शिकायत याचिका से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एक कंपनी मेसर्स उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "संगठन" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत और निगमित है, जिसका मुख्यालय बैंगलोर में है। उक्त संगठन भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण और मार्गदर्शन में कार्य करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के तहत पंजीकृत एक सूक्ष्म वित्त संस्थान है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संगठन को गरीबी को कम करने के लिए गरीब ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के मिशन के साथ शामिल किया गया था। संगठन ग्राहकों द्वारा आवश्यक वित्तीय सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से कम आय वर्ग की महिला ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। यह किसी अन्य चिट फंड संगठन की तरह नहीं है। यह गैर-जमा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन. बी. एफ. सी.) है।

संगठन आर्थिक रूप से बहुत गरीब परिवार को उनके आर्थिक विकास और उनके छोटे व्यवसाय में निवेश के लिए ऋण देता है। यह ऋण सेविका, नौकरानी, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, छोटी दुकानों के मालिकों, कढ़ाई, सिलाई आदि करने वाली गरीब महिलाओं को दिया जाता है। संगठन का मुख्यालय बैंगलोर में है और अब इसकी पटना शहर सहित पूरे देश में तीन सौ शाखाएँ हैं।

4. प्रारम्भ में, यह याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो पहले एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए 2012 का डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 883 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था, लेकिन इस बीच, ओ. पी. संख्या 2 के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 182 और 211 के तहत कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश के साथ याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त करते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, उपरोक्त आपराधिक रिट को याचिकाकर्ताओं द्वारा वापस ले लिया गया था। इसके बाद 24.02.2015 के आदेश के अनुसार विरोध शिकायत के आधार पर, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पटना उच्च न्यायालय सी. आर. लिया। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बहुत ही यांत्रिक तरीके से आईपीसी की धारा 417 और 418 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान। इसलिए, वर्तमान याचिका।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता संगठन के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कंपनी अधिनियम 1956 (2013 में संशोधित) के तहत एक पंजीकृत कंपनी है जो वित्तीय गतिविधियों से संबंधित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले को दर्ज करने से पहले, याचिकाकर्ता नं. 1. आलोक कुमार, मनीष रंजन (शिकायतकर्ता/मुखबिर) और दीना कुमार के खिलाफ उच्च अधिकारियों से धन के दुरुपयोग के बारे में निर्देश प्राप्त करने के बाद जब वह कंपनी की शाखा पटना शहर में शामिल हुए। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता सं. 1, पटना सिटी चौक पी. एस. 2012 का मामला संख्या 12 उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 406,420,467,468 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज

किया गया था, जो जांच में सही पाए जाने पर तदनुसार आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। यह आगे बताया गया है कि सह-अभियुक्तों में से एक मनीष रंजन ने गलत और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से जवाबी कार्रवाई करते हुए पटना शहर के एसीजेएम के समक्ष एक शिकायत मामला दर्ज किया था, जिसे आईपीसी की धारा 406,420,467,468 और 120 (बी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2012 के शिकायत मामला संख्या 482 सी के रूप में दर्ज किया गया था, जिसे सी आर पी सी की धारा 156 (3) के तहत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच के लिए पुलिस को भेजा गया था। यह बताया गया है कि उक्त शिकायत पर पटना सिटी चौक पी. एस. मामला संख्या 49/2012 में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 467, 468 और 120(बी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसे जांच के बाद गलत पाया गया और जिसके बाद विरोध शिकायत याचिका पर, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 417 और 418 के तहत संज्ञान लेते हुए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान का वर्तमान विवादित आदेश पारित किया गया।

6. तर्क पर विचार करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शिकायत मामला संख्या 482c/ 2012, जो 2012 के पटना सिटी चौक पी. एस. केस नंबर 49 का आधार है, किसी भी हलफनामे के साथ समर्थित नहीं था और इसलिए एक मार्गदर्शक नोट लेकर **प्रियंका श्रीवास्तव और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** जैसा कि **[(2015) 6 एस. सी. सी. 287]** में बताया गया है। वर्तमान कार्यवाही निरस्त और अलग किए जाने योग्य है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संगठन को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था और केवल इसी आधार पर इस कार्यवाही को रद्द और अलग किया जा सकता है। प्रस्तुतियों के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ वकील ने **सुशील सेठी और एक अन्य बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जैसा कि **[(2020) 3 एससीसी 240]** में रिपोर्ट किया गया है।

7. विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने तर्क के माध्यम से आगे जोर दिया कि 24.02.2015 का संज्ञान आदेश स्पष्ट रूप से बिना कोई कारण बताए बहुत ही यांत्रिक तरीके से पारित किया गया प्रतीत होता है, जबकि जांच के लिए एक अलग और विचलित करने वाला नोट लिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यह भी एक प्रमुख आधार है, जिस पर ध्यान देकर वर्तमान कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है और अलग रखा जा सकता है। प्रस्तुतियों के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ वकील ने **रतन लाल पटेल बनाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और एक अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भरोसा किया जैसा कि **[(2022) 6 एस. सी. सी. 540]** में बताया गया है।

8. समग्रता में तर्क का सारांश देते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आपराधिक मामला/अभियोजन गुप्त और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से प्रतीत होता है, जो दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का एक स्पष्ट उदाहरण है और इसलिए **हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य 1992 सप्लीमेंट (1) 335, सुप्रीम कोर्ट के मामलों में** रिपोर्ट किए गए की स्थिति पर ध्यान देते हुए वर्तमान कार्यवाही रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के लिए उपयुक्त है।

9. प्रस्तुत आवेदन का विरोध करते हुए ओ. पी. संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा शिकायत याचिका में कहा गया है कि यह, प्रथम दृष्टया, सुझाव देता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 417 और 418 के तहत दंडनीय अपराध बनाए गए हैं और इसलिए एक मामले को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए, जहां याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 417 और 418 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया था, वहां व्यवधान डालने की आवश्यकता नहीं है।

10. इस स्तर पर इस मामले की बेहतर समझ के लिए आई. पी. सी. की धारा 417 और 418 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः-

417. धोखाधड़ी की सज़ा– जो कोई भी धोखा देता है, उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

418. यह जानते हुए छल करना कि इससे उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसके हित की रक्षा करने के लिए अपराधी आबद्ध है– जो कोई यह जानते हुए छल करेगा कि इससे उस व्यक्ति को सदोष हानि होने की संभावना है जिसके हित की रक्षा करने के लिए वह, या तो विधि द्वारा या विधिक संविदा द्वारा आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। जो कोई भी इस ज्ञान के साथ धोखा देता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को गलत नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी रुचि पटना उच्च न्यायालय सी. आर. को लेन-देन में है। जो धोखाधड़ी से संबंधित है, वह या तो कानून द्वारा, या एक कानूनी अनुबंध द्वारा, रक्षा करने के लिए बाध्य था, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

11. **प्रियंका श्रीवास्तव केस (सुप्रा)** के पैरा संख्या 30 और 31 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

30. *हमारी सुविचारित राय में, इस देश में एक ऐसा चरण आ गया है जहाँ धारा 156 (3) सी. आर. पी. सी. आवेदनों को मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले आवेदक द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना है। इसके अलावा, एक उपयुक्त मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट को सच्चाई की पुष्टि करने और आरोपों की सत्यता की पुष्टि करने की अच्छी*

तरह से सलाह दी जाएगी। यह शपथ पत्र आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। हम ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि इस तरह के आवेदन केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए नियमित रूप से दायर किए जा रहे हैं। कोई भी जिम्मेदारी लेना। इसके अलावा, यह और भी अधिक परेशान करने वाला और चिंताजनक हो जाता है जब कोई ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है जो किसी वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहे हैं, जिसे उक्त अधिनियम के ढांचे के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। लेकिन किसी आपराधिक अदालत में अनुचित लाभ उठाने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है जैसे कि कोई व्यक्ति बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प है।

31. *हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर करते समय धारा 154 (1) और 154 (3) के तहत पूर्व आवेदन होने चाहिए। आवेदन में दोनों पहलुओं को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और इस आशय के आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाने चाहिए। एक निर्देश देने के लिए वारंट कि धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन को एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए ताकि आवेदन करने वाला व्यक्ति सचेत हो और यह भी देखने का प्रयास करे कि कोई गलत हलफनामा नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब कोई हलफनामा झूठा पाया जाता है, तो वह कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। यह उसे धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार को आकस्मिक रूप से लागू करने से रोकेगा। इसके अलावा, हम पहले ही कह चुके हैं कि मामले के आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसकी सत्यता को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भी सत्यापित किया जा सकता है। हम राजकोषीय क्षेत्र, वैवाहिक विवाद/पारिवारिक*

विवादों, वाणिज्यिक अपराधों, चिकित्सा लापरवाही के मामलों, भ्रष्टाचार के मामलों और आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/अड़चनों से संबंधित कई मामलों के रूप में ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं, जैसा कि ललिता कुमारी [(2014) 2 एस. सी. सी. 1:(2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 524] में दर्शाया गया है। इसके अलावा, विद्वान मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के बारे में भी पता होगा।

12. इसके अतिरिक्त सुशील **सेठी केस (सुप्रा)** के पैरा संख्या 7.2, 7.5, 8.1 और 8.2 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

"7.2.वेसा होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम केरल राज्य, [(2015) 8 एस. सी. सी 293], *इस न्यायालय ने यह देखा और माना है कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरू से ही कोई धोखा हुआ था। यह भी देखा और माना है कि धोखाधड़ी का अपराध गठित करने के उद्देश्य से, शिकायतकर्ता को यह दिखाना आवश्यक है कि वादा या प्रतिनिधित्व करते समय अभियुक्त के पास धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा था। यह भी देखा और माना है कि ऐसे मामले में भी जहां अभियुक्त की ओर से अपना वादा निभाने में विफलता के संबंध में आरोप लगाए जाते हैं, प्रारंभिक वादा करते समय दोषपूर्ण इरादे की अनुपस्थिति में, धारा 420 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है। यह भी देखा और माना है कि वास्तविक परीक्षण यह है कि शिकायत में आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं।*

7.5. ***शरद कुमार सांघी बनाम संगीता राणे, [(2015) 12 एससीसी 781]*** *में, इस न्यायालय के पास आपराधिक प्रबंध निदेशक या किसी कंपनी*

के किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने पर विचार करने का अवसर था, जहां कंपनी को शिकायत में पक्षकार के रूप में नहीं रखा गया था। उपर्युक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया और माना गया कि प्रबंध निदेशक के खिलाफ प्रतिनिधिक दायित्व के विशिष्ट आरोप की अनुपस्थिति में, कंपनी को पक्षकार के रूप में नहीं रखे जाने की अनुपस्थिति में, ऐसे प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। यह भी देखा गया और माना गया कि जब कोई शिकायतकर्ता किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या किसी अधिकारी को फंसाने का इरादा रखता है, तो प्रतिनिधिक दायित्व का गठन करने के लिए अपेक्षित आरोप लगाना आवश्यक है।

8.1. *जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 420 सहपठित धारा 120-बी आईपीसी के तहत अपराधों के लिए आरोप-पत्र दायर किया गया है। हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एफआईआर और/या यहां तक कि आरोप-पत्र में कोई विशिष्ट आरोप और कथन नहीं है कि आरोपी का धोखाधड़ी और बेईमान इरादा लेनदेन की शुरुआत से ही था। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेसर्स एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड और सरकार के बीच अनुबंध तीन बिजली उत्पादन इकाइयों सहित नूरंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट की आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए था। अपीलकर्ताओं ने परियोजना के लिए टर्बाइन किसी अन्य निर्माता से खरीदे। कंपनी ने उक्त टर्बाइनों का उपयोग बिजली परियोजना में किया। अनुबंध वर्ष 1993 में हुआ था। इसके बाद वर्ष 1996 में परियोजना चालू हुई। वर्ष 1997 में, विद्युत विभाग ने परियोजना के निष्पादन पर संतुष्टि प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया। यहां तक कि दोष दायित्व*

अवधि भी जनवरी 1998 में समाप्त हो गई थी। वर्ष 2000 में, तीन टर्बाइनों के संबंध में कुछ दोष पाया गया था। तुरंत, टर्बाइनों को बदल दिया गया था। बिजली परियोजना ने शुरुआत से ही काम करना शुरू कर दिया था - 1996 से। यदि कंपनी/अपीलकर्ताओं का इरादा अरुणाचल प्रदेश सरकार को धोखा देना था, तो वे उन टर्बाइनों को नहीं बदलते जो दोषपूर्ण पाए गए थे। किसी भी मामले में, शिकायत में कोई विशेष आरोप या कथन नहीं है कि अनुबंध में प्रवेश करते समय अभियुक्त का धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा था। इसलिए, उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला भी बनता है।

8.2. *यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मुख्य आरोप कंपनी के विरुद्ध कहे जा सकते हैं। कंपनी को पक्ष नहीं बनाया गया है। आरोप क्रमशः कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशक तक सीमित हैं। प्रबंध निदेशक या निदेशक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं। प्रतिनिधि दायित्व गठित करने के लिए कोई आरोप नहीं हैं।* ***मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य [मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य, (2008) 5 एससीसी 668: (2008) 2 एससीसी (सीआरआइ) 692]*** *में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया है और माना गया है कि दंड संहिता में प्रबंध निदेशक या कंपनी के निदेशकों की ओर से प्रतिनिधि दायित्व संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं है, जब अभियुक्त कंपनी ही हो। यह भी देखा गया है और माना गया है कि प्रबंध निदेशक और निदेशक की प्रतिनिधि दायित्व उत्पन्न होगी, बशर्ते कि कानून में इस संबंध में कोई प्रावधान मौजूद हो। यह भी देखा गया है कि कानून में निर्विवाद रूप से ऐसी प्रतिनिधि देयताओं को तय करने का प्रावधान होना चाहिए। यह भी*

देखा गया है कि उक्त उद्देश्य के लिए भी, शिकायतकर्ता के लिए आवश्यक आरोपों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो कि प्रतिनिधिक दायित्व के प्रावधानों को आकर्षित करेगा। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं के खिलाफ ऐसे कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं, जो क्रमशः कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक हैं। इन परिस्थितियों में भी, आरोपित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अलग रखने की आवश्यकता है। "

13. **भजन लाल केस** (सुप्रा) के पैराग्राफ संख्या 102 को पुनः उद्धृत करना भी समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:

"102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुन: प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर फॉर्मूले को निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार

किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावकारी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हो। "

14. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी आधिकारिक क्षमता में आई. पी. सी. की धारा 406,420,467,468 और 120 (बी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2012 का पटना सिटी चौक पी. एस. मामला संख्या 12 के रूप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया, जो जांच में सही पाया गया और तदनुसार ओ. पी. संख्या 2 के खिलाफ सह-अभियुक्तों में से एक के रूप में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जबकि गलत और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से जवाबी कार्रवाई के रूप में, बाद में 2012 का शिकायत मामला संख्या 482 ए. सी. जे. एम. पटना के समक्ष दायर किया गया। सिटी, जिसे जाँच के लिए पुलिस को भेजा गया था और आई. पी. सी. की धारा 182 और 211 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ओ. पी. नंबर 2 के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश के साथ गलत पाया गया था। तथ्यों के अवलोकन और कथन से और आरोपों की पृष्ठभूमि से भी यह पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 417 और 418 के तहत कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। तदनुसार, **भजन लाल केस (सुप्रा)** के पैरा 1, 5 और 7 में उल्लिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 24.02.2015 के संज्ञान के आदेश और उसके परिणामस्वरूप होने वाली सभी कार्यवाहियों को, याचिकाकर्ता के संबंध में, शिकायत मामला संख्या 518/2013 में पारित किया गया, जो पटना सिटी पीएस केस संख्या 49/2012 से उत्पन्न हुआ था, जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी-सह-अतिरिक्त मुंसिफ चतुर्थ, पटना के समक्ष लंबित था, को रद्द और अलग रखा जाता है।

15. आवेदन की अनुमति है।

16. इस फैसले की एक प्रति तुरंत विद्वत निचली अदालत को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस. त्रिपाठी/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।